विचार बिन्दु

अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं। –चाणक्य

राजस्थान में निवेश कैसे बढ़े?

प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि उसके प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाए ताकि न केवल राज्य को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने हेतु राजस्व प्राप्त हो अपितु नागरिकों को रोजगार भी मिले। गत कुछ वर्षों से बेरोजगारी चरम पर है, जिसके कारण उद्योगों में निवेश का महत्व पहले की अपेक्षा बढ़ा है।

निवेश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थानीय उद्यमियों द्वारा, अन्य राज्यों के निवेशकों द्वारा एवं विदेशी निवेश। जहां विदेशी निवेश को आकर्षित करने का महत्व है वहीं स्थानीय स्तर पर निवेश के द्वारा भी रोजगार की विपुल संभावना बढ़ाई जा सकती है।

राज्य में निवेश को तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व संभालते ही इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया है। इसी दृष्टिकोण से ''राइजिंग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट सम्मिट'' का आयोजन जयपुर में 9 से 11 दिसंबर, 2024 तक किया जा रहा है। इसकी तैयारी के सिलसिले में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के कई दल विभिन्न देशों जैसे जापान, कोरिया, सिंगापुर, यू ए ई, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने वहां के प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा की। विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जहां तक निवेश का प्रश्न है, वह विदेश के अलावा, भारत के विभिन्न राज्यों से भी आमंत्रित किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान के उद्यमियों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यहां से निकले हुए प्रमुख उद्योगपतियों में एल एन मित्तल, बिरला, बांगड़, सिंघानिया पिरामल, बजाज सम्मिलित हैं।

निवेश सम्मिट के लिए कुछ दिनों से जयपुर शहर को सजाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर पौधों के गमले रखे जा रहे हैं। जो अच्छी-खासी सड़के हैं, उन पर भी दोबारा कारपेटिंग किया जा रहा है। सड़क के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हें साफ-सुथरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह काम विशेषकर उन्हीं स्थानों पर किया जा रहा है, जहां से 'राइजिंग राजस्थान' में भाग लेने वाले विदेशी एवं भारतीय निवेशकों को ले जाया जाएगा। सरकार को यह पता होना चाहिए कि आज के मीडिया के युग में विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को जयपुर की वास्तविक स्थिति की जानकारी है। इस आलेख में हम यह प्रयास करेंगे कि निवेश के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंड क्या हैं?

सम्मेलन आयोजित करना और सम्मेलन के दिनों में जयपुर शहर को रंग रोगन कर चमका देने से विदेशी मेहमान, अल्प समय के लिए प्रभावित भले ही हो जाएं, किंतु इससे निवेश नहीं आता है। यदि केवल एम ओ यू करने से राज्य में निवेश आना होता तो अब तक कई सौ लाख करोड़ का निवेश, राजस्थान में हो चुका होता। सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि अब तक हुए निवेश सम्मेलनों में कुल कितनी राशि के एम ओ यू हुए और उनमें से कितने वास्तव में धरातल पर उतरे?

''राइजिंग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट सम्मिट'' से पूर्व, देश-विदेश में कई प्री सम्मिट आयोजित हो चुकी हैं जिनमें 5 लाख करोड़ से अधिक के एम ओ यू पहले ही हो चुके हैं। वास्तव में, निवेशकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है एवं छोटे-छोटे कार्यों के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, उस पर निर्भर करता है कि वे राज्य में निवेश करेंगे अथवा नहीं? इस हेतु वे वर्तमान में कार्यरत उद्यमियों के अनुभव को भी दृष्टिगत रखते हैं। सरकार के विभाग जहां एक ओर देश-विदेश से नया निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं पूर्व में जो निवेशक उद्योग लगा चुके हैं, उनके साथ ''घर की मुर्गी दाल बराबर'' जैसा व्यवहार करते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि निवेश चाहे राज्य के अंदर से आए, अन्य राज्यों से अथवा विदेश से, सबके साथ समान रूप से गरिमा पूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

सरकार ने हाल ही में निवेश आकर्षित करने हेतु कई नीतियां जारी की हैं। एक और जहां नए उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, वहीं वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के लिए भी काम करना, सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

नीतियों में निरंतरता भी, निवेश को आमंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी दल के बदलने से दीर्घकालीन नीतियों में किसी प्रकार का अंतर न आए, यह सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा, निवेशक, निवेश करने के पश्चात, स्वयं को ठगा सा महसूस करेंगे।

राज्य की नौकरशाही को, उद्यमियों के प्रति मित्रवत व्यवहार की संस्कृति अपनाने की जरूरत है। सरकार के सब संबंधित विभागों का एक ही सूत्र वाक्य होना चाहिए, ''अच्छा व्यवहार, तत्पर काम''। उद्यमियों के काम, तत्काल, बिना किसी परेशानी के करने की आवश्यकता है।

नियमों का सरलीकरण भी किया जाना आवश्यक है। सभी सरकारें, समय-समय पर 'सिंगल विंडो सिस्टम' की बात करती रही हैं, किंतु वास्तविकता में इसे धरातल पर लागू होते हुए बहुत कम ही देखा गया है। सिंगल विंडो का अर्थ ही यह है कि निवेशक को, अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उनकी ओर से यह काम राज्य सरकार का मनोनीत अधिकारी करे।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जयपुर में जिस प्रकार के सुधार कार्य एवं शहर को बेहतर बनाने के कार्य राइजिंग राजस्थान सम्मिट के लिए किए जा रहे हैं, वैसे ही लगातार होते रहें। यदि सम्मिट के बाद पुनः हालात पहले जैसे ही हो जाएं, तो यह निवेशकों के साथ एक प्रकार से धोखा ही होगा और इससे राज्य की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इस बार सरकार ने एक अच्छा कदम यह उठाया है कि प्रत्येक देश एवं अन्य प्रदेश से निवेश को आकर्षित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे एम ओ यू करवाने से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएंगे। इन अधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वे वर्तमान में कार्यरत उद्योगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करवाएं।

निवेश इस पर भी निर्भर करता कि राज्य में कानून- व्यवस्था की स्थिति कैसी है एवं 'ईज़ऑफ लिविंग' कितना है? जयपुर शहर में, यदि कोई पूरा भ्रमण कर ले, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि सार्वजनिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण और अनधिकृत वाहनों के कारण कितनी कठिनाई होती है? जिस प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी के देर लगे रहते हैं, उन्हें देखकर कोई भी निवेशक बार-बार राज्य में निवेश करने से पहले सोचेगा। उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकारी, कई बार अलग-अलग राज्यों से आते हैं एवं रहने के लिए उपयुक्त वातावरण यदि नहीं पाते हैं, तो वे यहां काम नहीं करना चाहते हैं। उपयुक्त विशेषज्ञों का अभाव निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जयपुर में जिस प्रकार के सुधार कार्य एवं शहर को बेहतर बनाने के कार्य राइजिंग राजस्थान सम्मिट के लिए किए जा रहे हैं, वैसे ही लगातार होते रहें। यदि सम्मिट के बाद पुनः हालात पहले जैसे ही हो जाएं, तो यह निवेशकों के साथ एक प्रकार से धोखा ही होगा और इससे राज्य की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तत्काल काम करने और अच्छे व्यवहार की संस्कृति ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक अधिकारी में परिलक्षित होनी चाहिए। वर्तमान में जो लोग यहां पर उद्योग चला रहे हैं, उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए तो वे राज्य के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। प्रबंध निदेशक, रीको के रूप में कार्य करते हुए मैंने यह अनुभव किया कि बहुत छोटे-छोटे कामों के लिए यदि अधिकारी, तत्परता से सहयोग करें तो उद्यमी बहुत राहत महसूस करते हैं।

राजस्थान में निवेश लाते समय, इस बात पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि केवल बहुत बड़ी पूंजी के निवेश से ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितनी भूमि राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उस पर प्रति एकड़ कितना रोजगार उपलब्ध होगा? सबसे प्रमुख समस्या, राज्य के समक्ष बेरोजगारी की है, और उसे दूर करने में वही उद्योग अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जहां पर रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। हजारों करोड़ निवेश करके भी यदि नाम मात्र का रोजगार मिले, तो उससे, निवेश के आंकड़ों में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसे रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक समीकरण बनाना होगा, जिसमें भूमि, पूंजी एवं रोजगार तीनों अवयवों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा। राज्य को सस्ती भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक है। उद्यान लगाने में भूमि की लागत कम होनी चाहिए। उन लोगों को हतोत्साहित करना होगा जो केवल भूमि में निवेश करना चाहते हैं और जिनकी रुचि उद्योग लगाने में नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभालते ही औद्योगीकरण में तेजी लाने के महत्व को समझा है और इस हेतु उन्होंने सघन प्रयास प्रारंभ किए हैं। इन प्रयासों को फलीभूत करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नौकरशाही, उद्योगपतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। पत्रावली पर कुछ भी निर्णय लेते समय, यह प्रश्न पूछना, अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा कि ''इससे मुझे क्या लाभ होगा?'' जो अधिकारी इस आधार पर निर्णय लेते हैं, वे प्रकरणों को तब तक लंबित रखते हैं जब तक कि उनसे कोई संपर्क न कर ले और उनकी 'इच्छाओं' की पूर्ति न कर दे। अधिकारियों द्वारा फाइल पर कुछ भी निर्णय लेते समय केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि ''इससे राज्य और राज्य की जनता को किस प्रकार से लाभ मिलेगा?''

जो अधिकारी 'अच्छा व्यवहार, तत्पर काम' के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उन्हें निवेशकों से सार्वजनिक रूप से सराहना मिलती है। इसका अनुभव मैने, स्वयं ने, रीको के प्रबंध निदेशक पद पर 3 वर्ष तक कार्य करते समय किया था। आज भी, मैने जापानी उद्योगों के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों तथा स्थानीय उद्योग संघों द्वारा लिखे गए, उन सराहना वाले पत्रों को सम्हाल रखा है, जो उन्होंने बहुत समय से लंबित महत्त्व पूर्ण समस्याओं के तत्काल निस्तारण होने पर लिखे थे।

आशा है, नौकरशाही की सकारात्मक सोच और सहायता करने की मानसिकता से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास अवश्य ही फलीभूत होंगे। सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह समय-समय पर एक रिपोर्ट राज्य के समक्ष प्रस्तुत करे कि जितने एम ओ यू हुए, उनमें से कितने वास्तव में धरातल पर उतरे और कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ?

''राइजिंग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट सम्मिट'' के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार को शुभकामनाएं। आशा है, इसके परिणाम स्वरुप, राज्य की जनता को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होंगे एवं वे तीव्रता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकेंगे। यह संभव है, यदि इस आलेख में दिए गए कुछ सुझावों पर ध्यान दिया जा सके।

–राजेन्द्र भाणावत,
पूर्व आई.ए.एस.
पूर्व प्रबंध निदेशक, रीको

कार्य प्रणाली व निर्णय प्रक्रिया बताती है, सत्ता की आकांक्षी कांग्रेस गलतियों से कुछ सीखना चाहती नहीं- (भाग-1)

महावीर सिंह

13 से 15 मई 2022 तक, कांग्रेस नें एक बड़ा चिंतन कार्यक्रम उदयपुर में रखा था। उस चिंतन में निकली चिंताओं व आगे के रॉड मैप के बारे में काफी चर्चाएं हुई।

इसी प्रकार से 2022 में राहुल गांधी नें भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस पर भी खूब चर्चाएं हुई।

इन दोनों ही घटनाक्रमों के सम्बंध में 12मई 2022 व 16 दिसम्बर 2022 के राष्ट्रदूत में इस लेखक के दो लेख छपे थे। इन लेखों के कुछ अंश, कांग्रेस की स्थिति के सम्बंध में आज भी उतने ही प्रसांगिक है।

(12 मई 2022 के राष्ट्रदुत में प्रकाशित---कांग्रेस का चिंताओं पर चिंतन-नव संकल्प शिविर) लेख के कुछ अंश:-

13 से 15 मई को भारत की ग्रन्डओल्ड पार्टी का एक चिंतन शिविर, राजस्थान के सुंदर शहर उदयपुर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 500 के करीब बड़े कांग्रेसी नेता भाग लेंगे।

---राज व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए,तभी सरकारों की मनमानियों, गलत जन विरोधी नीतियों पर अंकुश लगने की संभावनाएं बनती हैं। लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं में विश्वास करने वाले सत्ता पक्ष के भी बहुत से बड़े नेता मानते है कि एक सशक्त विपक्ष बहुत आवश्यक है किंतु यह काम सत्ता पक्ष को तो नहीं करना है न?

---वर्तमान में विपक्ष, बिना समन्वय के एक पूर्णतः निष्क्रिय, कांतिविहीन, दिशाविहीन जमावड़ा सा लगता है-- स्वर्गीय राजीव गांधी व कांग्रेस के प्रयासों से संवैधानिक संसोधनों के जरिये सत्ता नीचे गांवों, पँचायत समितियों-मंडलों, जिला परिषदों, स्थानीय निकायों तक पहुंचाने का रास्ता खुला।-- राज्यों में बड़े मठाधीस नेता इस प्रयास को पूर्ण रूप से सफल नहीं होने दे रहे।--

--- स्वतंत्रता आंदोलन के समय के बड़े नेताओं ने अपने कथनी और करनी से लोगों को हर प्रकार से विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी है और उनके लिए है।

--- कांग्रेस नें अनेक क्रांतिकारी, जन हितकारी नीतिया अपनायी और जनता नें उन पर विश्वास किया और लंबे समय तक कांग्रेस देश को चलाने का दायित्व सौंपा

---राजस्थान की बात करें तो-- जागीरों की समाप्ति, --कृषि कार्य कर रहे थे उन्हें खातेदार मालिक बना दिया। एस सी,एस टी के-, गरीबों के- - उत्थान की नीतियां, कार्यक्रम व कानून बनाये।-- न्यूनतम आवश्यकताओं-रोटी, कपड़ा और मकान- को केंद्र में रख कर मिनिमम नीड प्रोग्राम-- -सिंचाई-सड़क-कृषि विकास-विद्युत परियोजनाएं बनाई, पूर्ण की, उद्योगीकरण की मजबूत नीव रखी, डेजर्ट डेवलोपमेन्ट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के चलाए। बैंकों से ग्रामीणों को -- आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ी। बंधक श्रमिक उन्मुक्ति-कृषि जोतों पर सीलिंग के तथा शिक्षा का-सूचना का- खाद्य सुरक्षा के अधिकार-मनरेगा कानून बनाये और लागू किये। यह कांग्रेस राज के बिखरे हुए बेनेफिसियरी ग्रुप थे।

---किन्तु कांग्रेस नें बड़ी गलतियां भी की, जनता नें सजा दी, पुनः सत्ता भी दी। कांग्रेस नें पुनः कुछ गम्भीर गलतिया की और उनकी जो सजा जनता ने दी, वह अभी कांग्रेस भुगत रही है। 2014 से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और राज्यों में भी जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है। --भाजपा नें चतुराई से बड़े भिन्न लाभार्थी ग्रुप बना दिये, यह उसके नेतृत्व कुशलता का प्रतीक है। --

कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। वर्तमानं में वह विपक्ष का दायित्व निभाये। सत्ता प्राप्ति के लिए जनता के समक्ष, गांव-मोहल्ले तक अपनी नीतियां, कार्यक्रम पहुंचाये।

(क्या ऐसा होता दिख रहा है??

----कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी थी कि उसने अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों, कानूनों का प्रचार-प्रसार व सही क्रियान्वयन नहीं किया और उनका यथोचित श्रेय नहीं ले पाई।

----वर्तमानं सत्ता पक्ष जिस सिद्धत से अपने कार्यक्रमों के सम्बंध में ऐसा करता है, कांग्रेस या अन्य दलों को सीखना चाहिए।

---कांग्रेस को-- हमें न सिखाये, हमे उनसे सीखने की जरूरत नही -की मनसिकता को त्यागने की आवश्यकता है।

---कांग्रेस को जनता को यह बताना, समझना होगा कि कांग्रेस सत्ता पक्ष से ज्यादा अच्छे प्रकार से जनता की कठीनाइयों को समझती है और समाधान की बेहतर योजनाएं, कार्क्रम चलाएगी।

---जनता उस पर क्यों, कैसे विश्वास करे?? इसके लिए कांग्रेस के नेता अपने अचार-व्यवहार से, अहंकार त्याग कर-राजशाही लाइफ स्टाइल छोड़ कर और जनता के मध्य जाकर, छोटी-छोटी सभाएं, संगोष्ठियाँ कर, समझाइस कर जनता के गले यह बात उतारें।

---कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे, जिन पर स्पष्ट नीतियों, कमिटमेंट की आवश्यकता हैं: अत्यधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों से हटा कर कृषि का विविधि करण और किसान द्वारा उसे अपनाए जाने पर कुछ समय के लिए उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई की नीति, एमएसपी को विधिक अधिकार बनाने और क्रियान्वयन।

गत 20 वर्षों में एमएसपी नहीं मिलने से देश के किसानों को लगभग 45 लाख करोड़ रु का नुकसान हुआ है। इस कारण उन पर कर्जा बढ़ा है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट नीति किसानों को बताएं--कृषि इनपुट्स की कोस्ट्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरह त्रैमासिक आधार प्राकलन व तदनुसार एमएसपी का रेगुलर पुनरावलोकन--

कृषि बीमा योजना की समीक्षा, सरलीकरण --

सेटेलाइट इमेजरीज के आधार पर त्वरित आकलन व भुगतान

श्रमिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा नीतियां

राजकीय उपक्रमों में भले ही सरकारी शेयर होल्डिंग कम करके उन्हें चलाने का दायित्व प्राइवेट हाथों में दे दे किन्तु उनकी स्थायी भूसंपदा पर 100 प्रतिशत स्वामित्व सरकारी रहे,

सेनाओं और अन्य शस्त्र बलों की भूमियों का, निजी व्यवसायिक, आवासीय, उद्योगिक कार्यों हेतु उपयोग निषेध हो।

सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया यथावत जारी रखी जाए---लघु उद्योगों के सम्बंध में नीति--

लीनियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक--

न्यायिक प्रक्रियों में सुधार-निर्णयों में तीव्रता, आस्था के आधार पर न्यायिक निर्णयों पर रोक के लिए संवैधानिक संसोधन हो।

जिन आपराधिक विचाराधीन मामलों में 2,4,5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान हो तथा बंदी आधी सजा भुगत चुके उन्हें रिहा करने व अन्य प्रकार से जेलों की दशा सुधारने के सम्बंध मे --बिना कारण बताए, निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व निरुद्ध व्यक्ति पर डालने के अनेक केंद्रीय, राज्यों के कानून बना रखे है, बहुत से निर्दिषों को सालों निरुद्ध रखा जाता है

--एक न्यायोचित केंद्रीय कानून बने जिसमें आतंकी, राष्ट्र सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों व गैंगस्टर्स की असामाजिक गतिविधियों पर रोक भी लगे और त्वरित जांच, फैसले भी हों।

--नई शिक्षा नीति की समीक्षा कर सुधार--स्वास्थ्य का मूल अधिकार-- मंहगाई पर नियंत्रण की नीति--पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब व अन्य आइटम्स को जीएसटी के अंतर्गत लाने-- जलवायु परिवर्तन पर सुधारों सम्बन्धी एकीकृत नीति--

सवैधानिक संस्थओं व राष्ट्रीय स्तर की कानून-व्यवस्था -अपराधों की जांच एजेंसीज के जीरो दुरुपयोग की जनता द्वारा विश्वास करने योग्य नीति-

पुलिस रिफॉर्म्स के जरिये पुलिस पर से राजनीतिक नेताओं का शिकंजा समाप्त करने (तेरी पुलिस-मेरी पुलिस का खेल समाप्त हो)।

--धार्मिक स्थलों तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक जुलूसों सार्वजनिक स्थलों पर करने के सम्बंध में समान-स्पष्ट नीति--यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक बहस चालू करवा दी गई है, कांग्रेस को उस पर भी अपनी समन्वित नीति साफ करनी होगी--लोककपाल संस्था को सशक्त करने--भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस--कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर जिस से जनता विश्वास करे --धंदे के लिए राजनीति करने वालों से पीछा छुड़ाओ-महिलाओं को निर्वाचन वाली संस्थाओं और सरकारी नोकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण

--मध्यम जातियां---:: किसी समय यह कांग्रेस की रीढ़ हुआ करती थी किन्तु कांग्रेस में निहित स्वार्थियों नें इन जातियों को सत्ता में सम्मानपूर्ण भागीदारी नही दी और शनैः शनैः यह जातीयां कांग्रेस से विमुख हो गई। यूपी में चौधरी चरण सिंह के कांग्रेस छोड़ने के उपरांत व जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तथा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे जनता के मानस पर छा गए और उतरी भारत में कांग्रेस का पतन प्रारम्भ हो गया।

इन जातियों को, राज में पर्याप्त-सम्मान पूर्ण भागीदारी के, केवल सिबोलिज्म के आधार पर कोई पार्टी, अब अपने साथ नही रख सकती।

ऐसी ही गलतियां अब भी दोहराई जा रही है। जिन जातीयों का विधान सभा में 0.5 प्रतिशत से 5,7 प्रतिशत तक ही प्रतिनिधित्व सत्ता पक्ष में हो उसको 100 प्रतिशत सत्ता कैसे?

मीडिया प्रबन्धन:-

कांग्रेस के लिए यह उसके हित में होगा कि विशुद्ध धार्मिक मुद्दों पर व विशिष्ट प्रायोजित नैरेटिव्स पर बहसों नें भाग नही ले। आज अधिसंख्य मीडिया पर्चेजेबल, मैनेजेबल है, जहां लाभ दिखेगा, उनकी बात की बीन बजाएगा।

बहुत से अन्य मुद्दों पर भी, कई बार ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि सत्ता पक्ष द्वारा बिछाई चौसर पर, कांग्रेस उनके ही चक्रव्यूह में नादानी से फंसती है।

इन सब व अन्य जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की क्या नीतियां है, किसी भी स्वघोषित बड़े नेता को बोलते सुना? कांग्रेस को यह भ्रम छोड़ देना चाहये कि जनता उन्हें बाई डिफ़ॉल्ट सत्ता सौंप देगी।

ऐसा नहीं होगा क्योंकि सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व का प्रबंधन ऐसा है कि इसकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन से जनता सन्तुष्ट दिखती है और अभी तक उस पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष का शीर्ष नेतृत्व गली-मौहल्लों, छोटे कस्बों से आया है, उनमें आम आदमी से जुड़ने की अदभुत क्षमता है और हाल फिलहाल विपक्ष के पास इसका तोड़ नहीं।

मोदी जी तो किसी भी सभा में खड़े होकर एक्सटेम्पोर 10,20 उपस्थितों के नाम गिना कर सीधे जन समूह से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस में किस नेता में यह क्षमता है???

वर्तमानं में सत्ता पक्ष नें धर्म आधारित विभाजनकारी नैरेटिव्स चला रखे है, उनकी स्टीम कम होने में समय लगेगा बशर्ते भाजपा चल कर कोई बहुत बड़ी गलती न करे। इस दौरान कांग्रेस को उस से जुड़े आम आदमीयों को जोड़े रखने होगा।

कांग्रेस 5,7 साल में एक आधी बार नुमाइसी चिन्तन शिविर न करके, वर्ष भर बूथ से लेकर उपर तक सभाएं, संगोष्ठियाँ करे, विचार-विमर्श करे, आवश्यकता के अनुसार नीतियों में परिवर्तन-संशोधन करे, नई नीतिया बनाये। नीति-, कार्यक्रम बनाने का अधिकार जनाधारविहीन नेताओं का विशेषधिकार न हो।

सदस्यता लेने की प्रक्रिया सतत रूप से चालू रखे, जो 3-4 साल तक लगातार सदस्य रहे उसे सक्रिय सदस्यता का एसईसीसी का कार्ड दें, 8-10 साल के सक्रिय सभी सदस्यों को राज्य स्तरीय कमेटी का सदस्य बनाया जाए। वर्तमानं में चलने वाली मेरे सदस्य-तेरे सदस्य और कुछ नेताओं के कहने मात्र से ब्लॉक जिला, प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त करने की परिपाटी पर पुनर्विचार करे। एक निश्चित समयावधि तक सक्रिय सदस्य रहने वालों को ही पदाधिकारी बनाए।वर्तमानं में डिजिटल युग में इस प्रकार का डेटा संधारण व उसका समुचित उपयोग सम्भव है। कांग्रेस हर स्तर पर अपने संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाये, 50 प्रतिशत की ओर ले जाती दिखे।

कांग्रेस को विचारों के आदान-प्रदान का खुला मंच बनाएं। बुनियादी मुद्दों पर, संयमित भाषा में विचार प्रगट करने को नेतृत्व की आलोचना नहीं मानी जाए और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो।

कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी को विस्तृत करे, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों यथा लेखक, कलाकार, वकील, वरिष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स, वैज्ञानिक, विभिन्न समदायों के लोगों को शामिल करें। इसकी यदा-कदा बैठके न करके, नीति निर्माण -सतत समीक्षा की सक्रिय सर्वोच्च संस्था बनाये।

----अगर दूसरी पार्टियों नीतियां कार्यक्रम अच्छे है, उन का संगठन सक्रिय, मजबूत है तो कांग्रेस उनसे कुछ सीख ले-हमे सीखने की जरूरत नहीं, यह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी की ताकत उसके ग्राम-,मोहल्ले स्तर के कार्यकर्ता है। उन्हें सम्मान दें।

भजपा का तो बुथ स्तर तक संगठन सक्रिय है, कांग्रेस का बूथ स्तर पर है कोई संगठन? कार्यकर्ताओं को सुनना, सम्मान देना, उनके काम करना, यह तो, अब कांठोस के अहंकारी नेताओं को भाजपा से सीखना ही पड़ेगा।??

12 मई के लेख में जो बिन्दु उठाए थे, उस दिशा में से शायद ही किसी पर कोई कार्यवाही हुई हो। आज भी अधिकांस बूथों पर कांग्रेस का मजबूत संगठन नही। ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर स्थापित नेताओं के मरजिदनों के अलावा, ऊर्जावान, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती। एक परिवार एक पद का सिद्धांत दिखावा मात्र। कांग्रेस गांव, मोहल्ला, ब्लॉक, जिला स्तर पर जन हित के मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन करती दिखी नहीं। खानापूर्ति के लिए जिला स्तर पर या राजधानियों में यदाकदा 100, 50 आदमियों को झुंड में देखा जा सकता है। केवल सोशल मीडिया व चुनाव घोषणा पत्रों से आम आदमी को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

क्रमशः----

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

डी.एल.एड. प्रथम वर्ष का रिजल्ट 15 दिसम्बर तक आने की उम्मीद

बीकानेर, (निसं)। राज्य के 377 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 25 हजार अभ्यर्थियों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 30 नवंबर को खत्म हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के साथ ही पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 25 हजार अभ्यर्थियों की कॉपियां जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

डीएलएड प्रथम वर्ष के क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षा विभाग ने एनसीटीई की मान्यता के अनुसार योग्यताधारी पात्र परीक्षकों से 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सरकारी और निजी डीएलएड कॉलेजों में कार्यरत एमएड व एमए इन एजुकेशन योग्यताधारी शिक्षक रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। इन संस्थाओं से रिटायर्ड शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे।

राजस्थान की बेटियों ने शूटिंग बॉल में इतिहास रचा

भीलवाड़ा, (निसं)। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूंटिंगबॉल चैंपियनशिप बालिका वर्ग अंडर-17 बोधगया बिहार में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान की बेटियों ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं बालक वर्ग में राजस्थान चौथे पायदान पर रही। शूटिंग बॉल संघ के महासचिव ओपी माचरा, संरक्षक शिवराज सिंह, जयपुर संघ के सचिव संग्राम सिंह ओ पी ओबेरॉय ने खुशी जताई। जिला शूटिंग बॉल संघ भीलवाड़ा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा सचिव परमवीर सिंह बल्ला ने बताया कि संघ के पदाधिकारी श्रवण खटीक, अर्जुन रेगर, अविनाश खटीक, हनुमान सिंह गोखरू, रोहित, दिनेश, विजय धाबाई, लक्ष्मण, राजेंद्र आदि ने टीम कोच, मैनेजर और सभी को बधाई प्रेषित की।

राशिफल मंगलवार 3 दिसम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, मूल नक्षत्र सायं 4:42 तक, शूल योग दिन 3:08 तक, कौलव करण दिन 1:10 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग सायं 4:42 से आरम्भ होगा। आज से जमादि-उलमानि मु.मास 6 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:40 से 10:58 तक, लाभ-अमृत 10:58 से 1:35 तक, शुभ 2:53 से 4:11 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:04, सूर्यास्त 5:29

मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कन्या

घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी।

धनु

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मनःस्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कुंभ

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।